पूर्ण पीठ

न्यायमूर्ति डी. के. महाजन, बाल राज तुली और सी. जी. सूरी के समक्ष

बंता सिंह, आदि,-अपीलकर्ता।

बनाम

हरभजन कौर, आदि,-प्रतिवादी।

1969 का पत्र पेटेंट अपील संख्या 385।

6 मार्च 1974.

पंजाब प्री-एम्प्शन एक्ट (1913 का 1) - धारा 15 - सिविल प्रक्रिया संहिता (1908 का अधिनियम संख्या V) - आदेश 6 नियम 17 - प्री-एम्प्शन के लिए मुकदमा - डीजेनैंट-वेंडी ने मुकदमे के संबंध में प्रारंभिक चरण में आपत्ति उठाई आंशिक प्री-एम्प्शन के लिए बुरा होना - वादी-प्री-एम्प्टोर द्वारा आपत्ति के बावजूद वाद-पत्र में संशोधन के लिए आवेदन न करना - आंशिक प्री-एम्प्शन के लिए मुकदमा खारिज कर दिया जाना - वाद का संशोधन - क्या अपीलीय न्यायालय द्वारा कानूनी रूप से अनुमति दी जा सकती है।

अधिनिर्धारित किया गया कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 6 नियम 17 के तहत एक वाद या लिखित बयान में संशोधन की अनुमति देने के लिए, विचार करने वाला पहला बिंदु यह है कि क्या संशोधन के लिए आवेदन को ठोस बनाया गया है। संशोधन की अनुमति देने का एक अन्य नियम यह है कि वादपत्र में किसी भी संशोधन की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए यदि इसका प्रभाव किसी मूल्यवान अधिकार को छीनना है जो समय बीतने के कारण विपरीत पक्ष को प्राप्त हुआ है। आंशिक प्री-एम्प्शन का मुकदमा सक्षम नहीं है। इस तरह के मुकदमे को खारिज कर दिया जाना चाहिए और यदि इसे उस आधार पर खारिज कर दिया जाता है, तो प्रतिशोधी-प्रतिवादी को एक बहुत ही मूल्यवान अधिकार प्राप्त होता है, क्योंकि उस संपत्ति को बनाए रखने का उसका अधिकार अपरिहार्य हो जाता है। यदि वाद-विवाद में संशोधन की अनुमति देकर उस अधिकार को ख़तरे में डाल दिया जाता है, तो उसके साथ घोर अन्याय होता है, जिसकी भरपाई लागत के पुरस्कार से नहीं

की जा सकती। इसलिए जहां प्री-एम्प्शन के लिए एक मुकदमे में, प्रतिवादी प्रतिवादी मुकदमे को आंशिक प्रीएम्प्शन के लिए खराब होने के बारे में आपत्ति उठाता है, वादी-प्री-एम्प्शन, आपत्ति के बावजूद वादपत्र में संशोधन नहीं करता है और मुकदमा आंशिक प्री-एम्प्शन के लिए खारिज कर दिया जाता है। आंशिक प्री-एम्प्शन के दोष को दूर करने के लिए वादपत्र में संशोधन को अपीलीय न्यायालय द्वारा कानूनी रूप से अनुमति नहीं दी जा सकती है। यदि संशोधन की अनुमति दी जाती है तो अपीलीय न्यायालय अवैधता करता है।

(पैरा 7 और 21)

अभिनिर्धारित किया गया, (न्यायधीश सूरी, के अनुसार), कि इसे सार्वभौमिक अनुप्रयोग के नियम के रूप में निर्धारित नहीं किया जा सकता है कि उन सभी मामलों में जहां एक प्री-एम्प्टर विपरीत पक्ष द्वारा प्रारंभिक चरण में आंशिक प्री-एम्प्शन का दोष इंगित किए जाने के बाद परीक्षण के दौरान अपने वाद में संशोधन की मांग करने में विफल रहा है, उसे अपीलीय चरण में उस संशोधन की मांग करने से रोक दिया जाएगा। यह प्रत्येक व्यक्तिगत मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है कि संशोधन की अनुमति दी जाए या नहीं।

(पैरा 30)

13 जुलाई, 1971 को माननीय श्री न्यायमूर्ति डी.के. महाजन और माननीय श्री न्यायमूर्ति एच.आर. सोढ़ी की खंडपीठ द्वारा कानून के एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर निर्णय लेने के लिए मामले को पूर्ण पीठ को भेजा गया। पूर्ण पीठ में शामिल माननीय एमटी न्यायमूर्ति डी.के. महाजन, माननीय श्री न्यायमूर्ति बाल राज तुली और माननीय श्री न्यायमूर्ति सी.जी. सूरी ने अंततः 6 मार्च 1974 को मामले का फैसला किया।

1967 का आर.एस.ए.क्रमांक 1477, दिनांक 8 मई, 1969, में माननीय श्री न्यायमूर्ति गुरदेव सिंह की अदालत के आदेश से लेटर्स पेटेंट अपील के खंड X के तहत, श्री सरूप चंद गोयल, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, करनाल के दिनांक 4 दिसंबर, 1967 को संशोधित करते हुए, श्री वी.के. जैन,

उप-न्यायाधीश, प्रथम श्रेणी कैथल, दिनांक 25 अक्टूबर, 1966 के आदेश को उलट देता है। (वादी को प्री-एम्प्शन द्वारा कब्जे के लिए एक डिक्री प्रदान करना, जिसमें वादी द्वारा बिक्री प्रतिफल के रूप में 38,605 रुपये जमा करने की शर्त पर निचली अदालत में उसके द्वारा पहले से जमा की गई किसी भी राशि को घटाकर शामिल किया गया था। प्रतिवादी-प्रतिवादियों को भुगतान के लिए 5 फरवरी 1968 तक स्टांप और पंजीकरण शुल्क के रूप में 4,839.75 पैसे रुपये और इस तरह जमा किए जाने पर, उसका स्वामित्व उसकी भूमि पर जमा हो जाएगा और आगे आदेश दिया गया कि यदि वह उपरोक्त शर्त के अनुसार राशि जमा करने में विफल रही, तो उसका मुकदमा खारिज कर दिया जाएगा और पार्टियों को प्रत्येक मामले में अपनी लागत स्वयं वहन करने के लिए छोड़ दिया जाएगा) इस हद तक कि वादी को 6,227 रुपये के भुगतान पर 43 कनाल, 4 मरला की डिक्री दी जाती है।

यह भी आदेश दिया गया है कि यदि राशि पहले ही जमा नहीं की गई है तो इसका भुगतान 30 दिनों के भीतर किया जाएगा और यदि वादी निर्धारित समय के भीतर यह राशि जमा करने में विफल रहती है, तो उसका मुकदमा खारिज कर दिया जाएगा। आगे आदेश दिया गया है कि पार्टियां अपनी लागत स्वयं वहन करेंगी।

अपीलकर्ताओं की ओर से तीरथ सिंह, अधिवक्ता।
सी. एल. लखनपाल, पी. सी. खुंगर और डी. एस. कीर, अधिवक्ता, (प्रतिवादियों के लिए)।

निर्णय

न्यायधीश तुली,–(1) इस पीठ के समक्ष निर्धारण के लिए कानून का एकमात्र प्रश्न है:–
क्या विद्वान निचली अपीलीय अदालत ने वादी-प्रतिवादी को अपीलीय स्तर पर अपने वाद में संशोधन करने की अनुमति देकर सही किया था, जब प्रतिवादी-अपीलकर्ताओं ने अपने लिखित बयान में मुकदमे के आंशिक प्री-एम्प्शन के खराब होने के संबंध में आपत्ति उठाई थी और वादी-प्रतिवादी, इसके बावजूद, तब तक यह कहता रहा, जब तक कि मुकदमा विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा खारिज नहीं कर दिया गया, कि विक्रेता द्वारा विक्रेताओं को केवल 5 कोठे बेचे गए, न कि 6?

(2) संक्षेप में बताए गए तथ्य यह हैं कि अर्जन सिंह और उनके तीन भाई, अमर सिंह, सुरजन सिंह और गुरमेज सिंह और उनकी मां श्रीमती खेम कौर ने बंता सिंह और अन्य (अपीलकर्ताओं) को 38,605 रुपये में 307 कनाई 6 मरला जमीन, 5 कच्चे कोठे और 1 पक्का कोठा के साथ बेच दिया। 20 अगस्त, 1964 को पंजीकृत बिक्री-विलेख। विक्रेता, अर्जन सिंह की बेटी श्रीमती हरभजन कौर ने कुल 38,605 रुपये का भुगतान करके उक्त भूमि के 6 के बजाय 307 कनाल 6 मरला और 5 कोठों के कब्जे के लिए मुकदमा दायर किया। उस मुकदमे का प्रतिवादियों द्वारा विरोध किया गया था और एक दलील यह दी गई थी कि मुकदमा आंशिक छूट के लिए बुरा था। यह दलील लिखित बयान में प्रारंभिक आपत्ति संख्या 3 में कही गई थी और वाद पत्र के पैराग्राफ 2 के उत्तर में, विक्रेताओं ने स्पष्ट रूप से कहा था कि जमीन के साथ 6 कोठे बेचे गए थे, न कि 5 जैसा कि वाद पत्र में कहा गया है। अपनी प्रतिकृति में, वादी-प्रतिवादी ने दावा किया कि विक्रेताओं द्वारा उठाई गई प्रारंभिक आपत्ति संख्या 3 गलत थी और उसे अस्वीकार कर दिया गया था और लिखित बयान के पैराग्राफ 2 के उत्तर में, उसने दोहराया कि बिक्री-पत्र के अनुसार, 5 कोठे बेचे गए थे और नहीं 6 थे। तदनुसार एक अंक इस प्रकार तैयार किया गया: -

"क्या आंशिक प्री-एम्प्शन के लिए मुकदमा ख़राब है?" वादी-प्री-एम्प्टर ने 17 अगस्त, 1965 को विक्रय-पत्र की प्रति के बिना मुकदमा दायर किया, लेकिन 8 अक्टूबर, 1965 को उसकी प्रमाणित प्रति दायर की, जबकि प्रतिवादी-प्रतिवादियों ने 5 अक्टूबर को मूल विक्रय-लेख प्रस्तुत किया। 1966. बिक्री-विलेख में, जैसा कि विद्वान ट्रायल कोर्ट ने बताया है, यह कहा गया था कि विक्रेताओं ने 307 कनाल 6 मरला भूमि, 6 कोठों - 5 कच्चे और 1 पक्के - और सहायक अधिकारों, यानी , रास्ते का अधिकार, पेड़, पानी का नल आदि के साथ बेची थी। एक अन्य मुद्दा यह तय किया गया था कि क्या प्रतिशोधी-प्रतिवादियों द्वारा उठाई गई आपत्ति पर अदालत-शुल्क और क्षेत्राधिकार के प्रयोजनों के लिए मुकदमे का उचित मूल्यांकन किया गया था। वादी ने न्यायालय-शुल्क के प्रयोजन के लिए भूमि का मूल्य भू-राजस्व का 10 गुना (142.80 रुपये बढ़ा) और क्षेत्राधिकार के प्रयोजन के लिए भू-राजस्व का 30 गुना (428.40 रुपये बढ़ा) और 5 कोठा के लिए मुकदमा दायर किया गया जिसका मूल्य रु. 100 निर्धारित किया था। उस मूल्यांकन के अनुसार कोर्ट-फी का भुगतान किया गया था। अदालत-शुल्क और क्षेत्राधिकार के प्रयोजनों के लिए उचित मूल्यांकन के संबंध में मुद्दे को प्रारंभिक मुद्दे के रूप में पेश किया गया था और दोनों पक्षों के विद्वान वकील इस बात पर सहमत थे

कि विवाद में कोठों का बाजार मूल्य 500 रुपये था। वादपत्र के अनुच्छेद 7 में तदनुसार संशोधन किया गया और अपर्याप्त न्यायालय शुल्क की भरपाई की गई। हालाँकि, वादी के मुकदमे को 5 अक्टूबर, 1966 को विद्वान ट्रायल कोर्ट ने इस आधार पर खारिज कर दिया था कि यह आंशिक प्री-एम्प्शन के लिए बुरा था।"

(3) उस डिक्री के खिलाफ, वादी-प्री-एम्प्टर ने एक अपील दायर की, जिसे 4 दिसंबर, 1967 को विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, कमल ने स्वीकार कर लिया। अपील के ज्ञापन के साथ, वाद में संशोधन करने की अनुमति के लिए एक आवेदन भी दिया गया। ताकि 5 की जगह 6 कोठों का जिक्र किया जा सके, यह भी दाखिल किया गया। उस आवेदन में, यह कहा गया था कि वादी के वकील के पास विक्रय-पत्र की प्रति के अनुसार, 5 कोठे बेचे गए थे - 4 कच्चे और एक पक्का - और इस तरह गलती हुई थी। विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ने वादपत्र में संशोधन की अनुमति दी और मुकदमे का पूरा फैसला सुनाया। प्रतिवादियों ने इस न्यायालय में 1967 का आर.एस.ए.सं.1477 दायर किया, जिसे 8 मई 1969 को गुरदेव सिंह, जे. द्वारा आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया गया। विद्वान न्यायाधीश ने माना कि संशोधन को विद्वान निचली अपीलीय अदालत द्वारा उचित रूप से अनुमति दी गई थी, लेकिन वादी - प्रतिवादी केवल अपने पिता के हिस्से की सीमा तक बिक्री को प्री-एम्प्ट करने की हकदार थी, न कि पूरी बिक्री के लिए क्योंकि उसे अपने चाचाओं और दादी द्वारा की गई बिक्री को प्री-एम्प्ट करने का कोई अधिकार नहीं था। नतीजतन, बेची गई संपत्ति के 1/6 हिस्से के लिए 6,227 रुपये के भुगतान के खिलाफ एक डिक्री पारित की गई, यह राशि उस संपत्ति के क्षेत्र के अनुपात में थी जिस पर उसका पूर्व-खाली का अधिकार मौजूद पाया गया था।

(4) विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले और डिक्री के खिलाफ, प्रतिवादियों ने लेटर्स पेटेंट के खंड 10 के तहत वर्तमान अपील दायर की, जिस पर वादी प्रतिवादी द्वारा क्रॉस-आपत्तियां दायर की गईं। वह अपील एक डिविजन बेंच (डी.के. महाजन और सोढ़ी, जे.जे.) के समक्ष सुनवाई के लिए आई और विद्वान न्यायाधीशों ने माना कि जिन प्रतिवादों को खारिज कर दिया गया, उनमें कोई योग्यता नहीं थी। प्रतिवादियों की अपील के संबंध में, पहला तर्क यह है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा वादी-प्रतिवादी को बिक्री मूल्य का 1/5 भाग जमा करने की अनुमति देने के समय का विस्तार

कानून की नजर में गलत था, जिसे खारिज कर दिया गया। दूसरा तर्क कि वाद-विवाद में संशोधन की अनुमति विद्वान निचली अपीलीय न्यायालय द्वारा नहीं दी जा सकती, इस मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि ऊपर कहा गया है, निर्णय के लिए एक बड़ी बेंच को भेजा गया था। इस तरह यह मामला इस बेंच के समक्ष सुनवाई के लिए रखा गया है।

(5) किसी वाद या लिखित बयान में संशोधन की अनुमति देने के लिए, विचार करने वाला पहला बिंदु यह है कि क्या आवेदन वास्तविक किया गया है। वर्तमान मामले में, विक्रेताओं ने, पहले अवसर पर, अपने लिखित बयान में, सटीक रूप से बताया कि 6 कोठे, न कि 5, जैसा कि वादपत्र में कहा गया है, विक्रेताओं द्वारा उनके पक्ष में बेचे गए थे और यह मुकदमा था उस आधार पर आंशिक पूर्व-मुक्ति के लिए बुरा है। वादी-प्री-एम्प्शनर का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित होने के बावजूद, वह अपनी प्रतिकृति में यह कहती रही कि आंशिक प्री-एम्प्शन के संबंध में आपत्ति गलत थी और इसलिए उसे अस्वीकार कर दिया गया था और जैसा कि विक्रय-पत्र में कहा गया था, केवल 5 कोठे बेचे गए थे। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि प्रतिकृति में 6 के बजाय 5 कोठों का दावा बिक्री-विलेख को ध्यान से पढ़े बिना किया गया था, जो बिक्री लेनदेन का प्रतीक था - प्री-एम्प्शन के लिए उसके मुकदमे की विषय-वस्तु। इसके बाद विद्वान ट्रायल कोर्ट ने इस बिंदु पर एक विशिष्ट मुद्दा तय किया और विक्रेताओं ने मूल विक्रय-पत्र प्रस्तुत किया जो उनके कब्जे में था। फिर भी वाद-विवाद में संशोधन हेतु कोई आवेदन नहीं किया गया। विद्वान विचारण न्यायालय ने विक्रय-पत्र में इस कथन के आधार पर कि 6 कोठे बेचे गए थे, वादी-प्रतिवादी के विरुद्ध मामले का निर्णय किया। मुक़दमे के ख़ारिज होने के बाद ही वादी को एहसास हुआ कि उसने ग़लती से यह कहा था कि केवल 5 कोठे बेचे गए थे, 6 नहीं। इन परिस्थितियों में, मैं यह नहीं मान सकता कि प्रथम अपीलीय न्यायालय में जो संशोधन मांगा गया था वह प्रामाणिक था। विशेष रूप से इसलिए क्योंकि वादी के वकील के पास मौजूद विक्रय-पत्र की प्रति यह दिखाने के लिए कभी प्रस्तुत नहीं की गई कि उसमें केवल 5 कोठों का उल्लेख किया गया था, 6 का नहीं, जिसके आधार पर वादी का मसौदा तैयार किया गया था। यह कहीं भी साक्ष्य में नहीं है कि वादी ने बेची गई संपत्ति का पता लगाने के लिए मुकदमा दायर करने से पहले विक्रय-पत्र की प्रमाणित प्रति प्राप्त की थी और जिसे प्री-एम्प्शन के लिए मुकदमे की विषय-वस्तु बनाया गया था। वादी द्वारा बाद में पेश की गई विक्रय-पत्र की प्रमाणित प्रति से पता

चलता है कि इसे 8 अक्टूबर, 1965 को तैयार किया गया था। इस प्रकार, यह नहीं कहा जा सकता कि गलती असावधानी के कारण हुई; कम से कम कहें तो, यह वादी और उसके वकील, जिन्होंने वादी का मसौदा तैयार किया था, की घोर लापरवाही और असावधानी के कारण था। किसी भी व्यक्ति, जिसका ध्यान स्पष्ट रूप से किसी तथ्य की ओर आकर्षित होता है, से अपेक्षा की जाती है कि वह संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से देखकर सही तथ्यों से अवगत होने के बाद ही उसका खंडन करे। भले ही वादी के वकील के पास मौजूद विक्रय-पत्र की प्रति सही प्रति न हो, विक्रेता द्वारा दायर मूल विक्रय-पत्र या वादी द्वारा स्वयं दाखिल की गई इसकी प्रमाणित प्रति का उसके वकील द्वारा निरीक्षण के दौरान निरीक्षण किया जा सकता था। के लिए परीक्षण विक्रेताओं द्वारा उठाई गई आंशिक छूट के संबंध में आपत्ति की सत्यता से स्वयं को अवगत कराएं। शंकर लाल बनाम दल्लू[1] में, पंजाब मुख्य न्यायालय की एक खंडपीठ ने कहा कि यदि मामले के बहुत देर से विक्रेताओं द्वारा आंशिक छूट की आपत्ति उठाई जाती है, तो न्यायालय द्वारा इस पर विचार नहीं किया जा सकता है। और यदि विचार किया जाता है, तो वादपत्र में संशोधन की अनुमति दी जानी चाहिए। वर्तमान मामले में, विक्रेताओं द्वारा यथाशीघ्र अवसर पर आपत्ति उठाई गई थी लेकिन वादी इस पर उचित ध्यान देने में विफल रही और उसने अपना मुकदमा खारिज होने तक वाद में संशोधन की मांग नहीं की।

(6) गुलाम कादिर और अन्य बनाम दित्ता और अन्य[2] मामले में लाहौर उच्च न्यायालय की एक पूर्ण पीठ ने निम्नानुसार टिप्पणी की: -

"अब इस बात पर विवाद नहीं किया जा सकता है कि प्री-एम्प्शन का अधिकार प्रतिस्थापन का अधिकार है और यदि कोई व्यक्ति उस अधिकार के प्रयोग में प्रतिशोध के लिए खुद को प्रतिस्थापित करना चाहता है, तो उसे उस पूरी संपत्ति पर दावा करना होगा जिस पर उसका अधिकार है (और ऐसे मामलों में जहां प्रतिशोधी प्री-एम्प्शनर भी होता है, एक श्रेष्ठ अधिकार) प्री-एम्प्शन का और उसके किसी भी हिस्से को अपने अधिकार को पूरी तरह से खोने के खतरे में नहीं छोड़ सकता है, इसके अलावा संपूर्ण संपत्ति के संबंध में प्रतिशोधी को प्रतिस्थापित नहीं किया

---

[1] 25 आई.सी. 68.

[2] (1945) 47 पी.एल.आर. 224.

जा सकता है, जिस पर उसका पूर्व-मुक्ति का अधिकार विस्तारित है या उसके पास पूर्व-मुक्ति का अधिमान्य अधिकार है और इस प्रकार, वह उस तरीके से कार्य करके संपूर्ण सौदेबाजी पर कब्ज़ा करने में विफल रहेगा, न केवल उन मामलों में एक अविभाज्य अनुबंध को तोड़ना जहां वह ऐसा नहीं कर सकता था, बल्कि अपनी चूक के परिणामस्वरूप, विक्रेता को संपत्ति के हिस्से के संबंध में बराबर या कभी-कभी बेहतर स्थिति बनाए रखने की अनुमति भी दे सकता है। जिसे वह भुनाना चाहता था। इसलिए, जिस सौदे को पूरी तरह से प्री-एम्प्टम्प्ट किया जाना था, उसे प्री-एम्प्शनर द्वारा विभाजित नहीं किया जा सकता था, सिवाय उन मामलों के जहां उसके पास केवल सीमित सीमा तक प्री-एम्प्शन का अधिकार या अधिमान्य अधिकार था, जैसा भी मामला हो, अर्थात बेची गई संपत्ति के एक हिस्से के संबंध में और जहां उसने इसे बिना किसी औचित्य के विभाजित किया, जैसा कि मैंने ऊपर उल्लेख किया है, यह घातक साबित होने के लिए बाध्य था और उसके पक्ष में डिक्री पारित नहीं की जा सकती थी। इसलिए, इसका मतलब यह होगा कि एक प्री-एम्प्टर को हमेशा उस अधिकतम का दावा करना चाहिए जिसके लिए वह हकदार है या उसके पास एक बेहतर उपाधि है और ऐसा करने में उसकी विफलता के परिणामस्वरूप उसका दावा इस आधार पर खारिज कर दिया जाएगा कि वह आंशिक प्रीएम्प्शन के लिए मुकदमा कर रहा था। ।"

इस निर्णय का अनुपात वर्तमान मामले के तथ्यों पर उपयुक्त और स्पष्ट रूप से लागू होता है।

(7) संशोधन की अनुमति देने का एक अन्य नियम यह है कि वाद-विवाद में किसी भी संशोधन की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए यदि इसका प्रभाव किसी मूल्यवान अधिकार को छीनना है जो समय बीतने के कारण विपरीत पक्ष को प्राप्त हुआ है। वर्तमान मामले में, जब निचली अपीलीय अदालत में संशोधन के लिए आवेदन किया गया था, तो प्री-एम्प्शन के लिए मुकदमा दायर करने का समय पहले ही समाप्त हो चुका था और विक्रेताओं के पक्ष में एक मूल्यवान अधिकार अर्जित हो चुका था। ऐसा प्रतीत होता है कि न्यायमूर्ति गुरदेव सिंह, जिनका निर्णय अपील के अधीन है, ने बाद में अपना विचार बदल दिया है, जैसा कि श्रीमती गुरदीप कौर बनाम केहर सिंह और अन्य[3] से स्पष्ट है। उस मामले में, प्रतिवादी ने दलील दी थी कि आबादी में स्थित कच्चा घर, जो बेची गई संपत्ति का हिस्सा था, को प्री-एम्प्शन के वाद में शामिल नहीं किया गया था, मुकदमा खारिज होने योग्य था क्योंकि

[3] 1971 पी.एल.आर. 384.

आंशिक प्री-एम्प्शन की अनुमति नहीं दी जा सकती थी। उस याचिका पर एक विशिष्ट मुद्दा इस प्रकार तैयार किया गया था: -
"क्या आंशिक प्री-एम्प्शन के लिए मुकदमा ख़राब है?"

(8) मुकदमे की सुनवाई आगे बढ़ी और जब सबूतों की जांच की जा रही थी, तो प्री-एम्प्टर ने वाद में संशोधन के लिए अदालत में आवेदन किया ताकि गांव की आबादी में स्थित कच्चे घर को राहत खंड और वाद पत्र के पैराग्राफ 1 दोनों में शामिल किया जा सके। वह आवेदन, जिसे मुकदमा दायर करने की सीमा अवधि समाप्त होने के लंबे समय बाद स्वीकार किया गया था, प्रतिवादी प्रतिवादी द्वारा जोरदार विरोध किया गया था और मामले पर उचित विचार करने के बाद, विद्वान परीक्षण न्यायाधीश ने मुख्य रूप से इस आधार पर संशोधन को अस्वीकार कर दिया कि यह एक मूल्यवान अधिकार समय बीतने के कारण प्रतिवादी के खाते में जमा हो गया था और वादी को अपनी याचिका में एक नई प्रार्थना शामिल करने की अनुमति देना उचित नहीं था। उस आदेश के खिलाफ कोई पुनरीक्षण दायर नहीं किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप विद्वान ट्रायल कोर्ट ने केवल इस निष्कर्ष पर मुकदमा खारिज कर दिया कि यह आंशिक पूर्व-खाली के लिए बुरा था, बिक्री-विलेख में बताए गए कच्चे घर को छोड़ दिया गया था। उस डिक्री के खिलाफ, प्री-एम्प्टर ने जिला न्यायाधीश की अदालत में अपील की और उस अपील के लंबित रहने के दौरान, वादपत्र में संशोधन की अनुमति के लिए एक आवेदन दायर किया गया था। उस आवेदन के पैराग्राफ 2 में कहा गया था:-
"26 मई, 1964 को विक्रय-पत्र के माध्यम से कथित तौर पर कच्ची जमीन को बेचने का आरोप लगाया गया था, जिसका उल्लेख वादी में नहीं किया गया था, हालांकि वादी ने मुकदमे में भूमि से जुड़े सभी अधिकारों के लिए मुकदमा दायर किया था, जैसा कि विक्रय-पत्र में उल्लेख किया गया है, लेकिन वादी ने कच्चे घर का उल्लेख नहीं किया है, जिसे विशेष रूप से विवादग्रस्त भूमि के साथ आवंटित किया गया था।"

(9) विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ने अपील स्वीकार कर ली और ट्रायल कोर्ट को संशोधन की अनुमति देने और उसके बाद गुण-दोष के आधार पर मुकदमे की सुनवाई आगे बढ़ाने का निर्देश दिया। उस आदेश के विरुद्ध एक अपील दायर की गई थी जिसे विद्वान एकल न्यायाधीश ने

स्वीकार कर लिया था। विभिन्न निर्णयों का उल्लेख करने के बाद रिपोर्ट के पैराग्राफ 11 में यह देखा गया है:-

"यह सच है कि संशोधन की अनुमति देने में न्यायालयों का मार्गदर्शन करने वाले सिद्धांतों में से एक यह है कि सभी संशोधनों की अनुमति दी जा सकती है यदि विपरीत पक्ष को लागतों से पर्याप्त मुआवजा दिया जा सकता है, लेकिन यह सिद्धांत संशोधन की अनुमति देते हुए, इस मामले में वादी के लिए कोई मदद नहीं करता है। विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ने मुकदमे को खारिज करने से रोक दिया था। संशोधन के लिए कोई भी लागत प्रतिवादी को उस स्थिति में नहीं रख सकती थी जिसमें वह संशोधन की अनुमति देने से पहले थी, क्योंकि ट्रायल कोर्ट के फैसले के अनुसार, आंशिक पूर्व-खाली के कारण मुकदमा विफल होना चाहिए।

(10) गुलजार सिंह और अन्य बनाम गुरबक्स सिंह और अन्य[4] मामले में न्यायमूर्ति आई. डी. दुआ द्वारा इसी तरह के एक मामले पर विचार किया गया था। उस मामले में, प्री-एम्प्शन की मांग की गई बिक्री 22 मई, 1963 को प्रभावी हुई थी और विक्रेता के भाई द्वारा प्री-एम्प्शन का मुकदमा 21 मई, 1964 को शुरू किया गया था। वादपत्र के पैराग्राफ 2 में यह स्पष्ट रूप से कहा गया था कि जोगिंदर सिंह, प्रतिवादी नंबर 3, ने वादी के पैराग्राफ 1 में उल्लिखित अपनी कृषि भूमि का एक चौथाई हिस्सा और उसी खेवट से संबंधित अहाता चाह का सोलहवां हिस्सा बेच दिया था। पैराग्राफ 1 में, यह दावा किया गया था कि गुरबक्स सिंह, कश्मीरा सिंह, बहादुर सिंह और जोगिंदर सिंह के पास खेवट नंबर 36 आदि से संबंधित कृषि भूमि थी। माना जाता है कि बिक्री एक पंजीकृत विलेख के माध्यम से की गई थी जिसका उल्लेख वादी में किया गया था। छूट के अधिकार का दावा इस आधार पर किया गया था कि वादी विक्रेता जोगिंदर सिंह का सगा भाई था और सह-हिस्सेदार भी था। 30 जुलाई, 1964 को लिखित बयान दायर किया गया था, जिसमें उठाई गई प्रारंभिक आपत्तियों में से एक यह थी कि मुकदमा आंशिक प्री-एम्प्शन के लिए बुरा था और उस आधार पर खारिज किया जा सकता था।

एक मुद्दा तैयार किया गया:-

"क्या मुकदमा आंशिक छूट के लिए है?"

---

[4] 5 मार्च, 1965 को सी.आर. नं. 33/1964 का निर्णय लिया गया।

पार्टियों के साक्ष्य के लिए कार्यवाही 25 सितंबर, 1964 तक के लिए स्थगित कर दी गई थी और उस तारीख को वादी द्वारा आदेश VI, नियम 17, सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत वादपत्र में संशोधन के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि वादपत्र के पैराग्राफ 2 में , शब्द "एक चौथाई हिस्सा" गलती से लिखा गया था और प्रतिवादी नंबर 3, जोगिंदर सिंह, उस जमीन का एकमात्र मालिक था जिसे उसने प्रतिवादी 1 और 2 के पक्ष में बेच दिया था। उस आवेदन के अनुसार, प्रतिवादी 3 जोगिंदर सिंह ने कभी भी एक चौथाई हिस्सा नहीं बेचा। उस आवेदन को, प्रतिवादियों के प्रतिरोध के बावजूद, इस आधार पर अनुमति दी गई थी कि चूक असावधानी के कारण हुई थी, और प्री-एम्प्शन मुकदमे में संपत्ति के गलत विवरण को संशोधन द्वारा ठीक किया जा सकता है, विद्वान न्यायाधीश ने उद्धृत विभिन्न निर्णयों पर विचार करने के बाद बार ने माना कि:-

"वादी को अपने वाद में संशोधन करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है यदि संशोधन का प्रभाव प्रतिवादी से कानूनी अधिकार छीनना होगा जो समय बीतने के बाद उसे प्राप्त हुआ है, लेकिन, कुछ हद तक आश्चर्यजनक रूप से, हालांकि विद्वान अधीनस्थ न्यायाधीश ने अनुपात के बल पर इसे स्वीकार कर लिया, वर्तमान मामले को उद्धृत सिद्धांत से बाहर निकालने में कामयाब रहे, यह देखते हुए कि मामला केवल लापरवाही और असावधानी का मामला था, वादी के वकील ने बिक्री-विलेख से परामर्श किए बिना वादी का मसौदा तैयार किया था। विद्वान न्यायाधीश द्वारा किए गए भेद की सराहना करना आसान नहीं है। यदि प्रतिवादी ने सीमा की समाप्ति के कारण निहित अधिकार प्राप्त कर लिया है और वादी केवल पूर्व-मुक्ति के आक्रामक अधिकार का दावा कर रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि, उच्चतम न्यायालय और इस न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांत के अनुरूप, कोई भी मामला वादी द्वारा संशोधन की अनुमति देने के लिए आवेदन किया गया था।"

(11) सुश्री काको बाई बनाम पहलाद[5] में, डी. फाल्शॉ, सी.जे. द्वारा निर्णय दिया गया, तथ्य यह थे कि 82 कनाल भूमि विक्रेताओं द्वारा 28 जून, 1960 को एक पंजीकृत बिक्री-विलेख द्वारा खरीदी गई थी। प्री -एम्प्र ने 23 अगस्त, 1960 को एक मुकदमा दायर किया और प्रतिवादियों ने अपने लिखित बयान में आपत्ति जताई कि यह मुकदमा आंशिक प्री-एम्प्शन के लिए बुरा था। यह तभी हुआ जब मुकदमा

---

[5] 1961 के सी.आर. नंबर 593 का फैसला 14 दिसंबर 1962 को हुआ।

लगभग समाप्त हो गया और 8 अगस्त, 1961 को बहस का चरण आ गया, कि वादी ने इस आधार पर अपने वाद में संशोधन करने के लिए आवेदन किया कि जिस भूमि के लिए उसने मुकदमा किया था, पंजीकृत विक्रय-पत्र की प्रमाणित प्रति जो उसने प्राप्त की थी उस क्षेत्र के संबंध में उसने एक वास्तविक गलती की थी और फर्द जमाबंदी जो उसने अपने वादपत्र के साथ दायर की थी, में निहित कुछ त्रुटियों के परिणामस्वरूप। मूल विक्रय-पत्र 12 मई, 1961 को दायर किया गया था, और आवेदन दायर करने से चार दिन पहले 4 अगस्त, 1961 को इसे औपचारिक रूप से प्रदर्शित किया गया था। ट्रायल कोर्ट ने माना कि एक वास्तविक गलती हुई थी और इसलिए, वादपत्र में संशोधन करने की अनुमति दी गई। विद्वान मुख्य न्यायाधीश ने निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ पुनरीक्षण याचिका स्वीकार कर ली: -

"याचिकाकर्ता की ओर से इस बात पर जोर दिया गया है कि वर्तमान मामले में किसी भी तरह की वास्तविक गलती की कोई संभावना नहीं है। प्रतिवादी द्वारा उठाई गई दलील से वादी को तुरंत सतर्क कर दिया जाना चाहिए था, जिसके संबंध में एक मुद्दा बनाया गया था कि मुकदमा आंशिक छूट के लिए बुरा था, और वादी मुकदमा दायर करने के पहले से ही भूमि के क्षेत्र के बारे में अच्छी तरह से जानता था कि मकान मालिक ने 82 कनाल भूमि से अपनी बेदखली के लिए राजस्व अदालत में मुकदमा दायर किया था, जिसमें से वादी ने उन कार्यवाही में स्वीकार किया था कि वह किरायेदार था। किसी भी मामले में, यह बताया गया है कि यद्यपि वादी द्वारा दायर विक्रय-पत्र की प्रतिलिपि में थोड़ी सी अशुद्धि है, यदि उस प्रतिलिपि में दिए गए फ़ील्ड के क्षेत्रों की जांच की जाती है और विस्तार से बताया गया है, तो यह पाया जाएगा उनका क्षेत्रफल कुल 82 कनाल बनता है। यह सरल जोड़ इस न्यायालय में वादी प्रतिवादी के विद्वान वकील द्वारा किया गया था और यह पाया गया कि दोषपूर्ण प्रतिलिपि में भी दिखाया गया क्षेत्र 82 कनाल था। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि वादपत्र में किसी भी संशोधन की अनुमति देने का कोई औचित्य नहीं था और मैं तदनुसार पुनरीक्षण याचिका स्वीकार करता हूं और लागत सहित आदेश को रद्द करता हूं।"

(12) ये टिप्पणियाँ वर्तमान मामले के तथ्यों पर बिल्कुल लागू होती हैं जैसे कि उस संदर्भ में की गई हों।

(13) इन निर्णयों के विरुद्ध, वादी-प्री-एम्प्टोर के विद्वान वकील ने प्रिगोंडा होंगोंडा पाटिल बनाम कलगोंडा शिडगोंडा पाटिल और अन्य[6], और ए.के. गुप्ता एंड संस लिमिटेड बनाम दामोदर वैली कॉर्पोरेशन[7] में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर भरोसा किया है, और प्रस्तुत किया है कि कार्रवाई का कोई नया कारण नहीं जोड़ा गया है और प्रतिशोधी-अपीलकर्ताओं को लागत से मुआवजा दिया जा सकता है। प्रिगोंडा होंगोंडा पाटिल के मामले (सुप्रा) में सुप्रीम कोर्ट के आधिपत्य ने माना कि कानून के सही प्रस्ताव किसनदास रूपचंद बनाम रचप्पा विठोबा[8] में न्यायमूर्ति बैचलर, द्वारा प्रतिपादित किए गए थे, जब उन्होंने पेज 649 और 650 पर कहा था:-

"सभी संशोधनों की अनुमति दी जानी चाहिए जो दो शर्तों को पूरा करते हैं (ए) दूसरे पक्ष के साथ अन्याय नहीं करना, और (बी) पार्टियों के बीच विवाद में वास्तविक प्रश्नों को निर्धारित करने के उद्देश्य से आवश्यक होना, लेकिन मैं निर्णय आगे उद्धृत करने से बचता हूं, मेरी राय में, वे सभी बिल्कुल एक ही सिद्धांत देते हैं। सिद्धांत, जैसा कि मैं इसे समझता हूं, यह है कि संशोधन को केवल तभी अस्वीकार किया जाना चाहिए जहां दूसरे पक्ष को उसी स्थिति में नहीं रखा जा सकता है जैसे कि दलील मूल रूप से सही थी, लेकिन संशोधन से उसे चोट लगेगी जिसकी भरपाई लागत में नहीं की जा सकती थी। यह केवल इस सामान्य नियम का एक विशेष मामला है कि जहां एक वादी कार्रवाई के कारण के संबंध में एक नया दावा स्थापित करके संशोधन करना चाहता है, जो कि मुकदमे की संस्था के बाद से सीमा से वर्जित हो गया था, संशोधन से इनकार कर दिया जाना चाहिए। इसकी अनुमति देने का मतलब प्रतिवादी को ऐसी चोट पहुंचाना होगा जिसकी भरपाई दावे के अच्छे बचाव से वंचित करके लागत के रूप में नहीं की जा सकती। इसलिए, अंतिम परीक्षा अभी भी वही है; क्या दूसरे पक्ष के साथ अन्याय किए बिना संशोधन की अनुमति दी जा सकती है, या नहीं?"

ये टिप्पणियाँ, वादी-प्रतिवादी की मदद करने से दूर, ऊपर उल्लिखित इस न्यायालय के निर्णयों को पूर्ण समर्थन देती हैं, जिसके आलोक में विद्वान निचली अपीलीय अदालत द्वारा वर्तमान मामले में

---

[6] ए.आई.आर.1957 1957 एस.सी.363.

[7] ए.आई.आर.1967 एस.सी. 96.

[8] आई.एल.आर. (1909)) 33 बम्बई 644।

अभिवचनों में संशोधन से संबंधित सुस्थापित और बार-बार दोहराए जाने वाले सिद्धांत के आधार पर अनुमत वाद-विवाद में संशोधन को न्यायिक रूप से उचित नहीं ठहराया जा सकता है।

(14) विद्वान वकील ने अपनी दलील के समर्थन में इस न्यायालय के कुछ निर्णयों पर भी भरोसा किया है कि संशोधन को प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा उचित रूप से अनुमति दी गई है और विवेकपूर्ण ढंग से प्रयोग किए गए उनके विवेक को अपील में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। सोढ़ी सिंह और अन्य बनाम बसंत सिंह और अन्य[9] में इस न्यायालय के फैसले का संदर्भ दिया गया है, जिसमें यह निर्धारित किया गया था कि जब बेची गई भूमि के कुल क्षेत्र के पूर्व-खाली के लिए एक मुकदमे में, वादी ने एक खसरा संख्या का उल्लेख करने के लिए, अनजाने में छोड़ दिया था, खसरा संख्या को शामिल करके वाद में संशोधन की अनुमति देना न्यायालय के लिए उचित था, जो कि बेची गई संपत्ति का केवल एक विस्तृत विवरण था। यह मामला स्पष्ट रूप से अलग है. उस मामले में, मुकदमे में भूमि के कुल क्षेत्रफल का सही उल्लेख किया गया था लेकिन एक खसरा नंबर अनजाने में छूट गया था। इसके अलावा, संशोधन की मांग मुकदमे के प्रारंभिक चरण में की गई थी - मुद्दों का निर्धारण - और मुकदमा खारिज होने के बाद नहीं। तेजा सिंह और अन्य बनाम भगवान सिंह[10] में, विक्रय-पत्र 19 अक्टूबर, 1964 को पंजीकृत किया गया था, और प्री-एम्प्शन का मुकदमा 19 अक्टूबर, 1965 को शुरू किया गया था। वादपत्र में, संपत्ति को प्री-एम्प्शन के लिए दायर किया गया था। -एम्प्टेड का सटीक वर्णन विक्रय-पत्र के उस भाग के अनुसार किया गया था, जो कि कीमत का भुगतान करने के तरीके के बारे में विवरण से पहले था। चाह भट्टियांवाला के बारे में वाद-पत्र में कोई उल्लेख नहीं किया गया था, लेकिन यह कहा गया था कि बिक्री के लिए वास्तव में भुगतान की गई कीमत 12,000 रुपये थी, हालांकि बिक्री-विलेख में इसे काल्पनिक रूप से 24,000 रुपये के रूप में दर्ज किया गया था। प्रतिवादियों की ओर से लिखित बयान 19 मार्च, 1966 को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था, जिसमें ली गई आपत्तियों में से एक यह थी कि मुकदमा आंशिक पूर्व-मुक्ति के लिए बुरा था। इसके तुरंत बाद वादी-प्री-एम्प्टर ने वाद में संशोधन की प्रार्थना करते हुए एक आवेदन प्रस्तुत किया ताकि चाह भट्टियांवाला को भी उस संपत्ति में शामिल किया जा सके, जिसकी उसने

---

[9] 1962 पी.एल.आर. 633.

[10] 1970 पी.एल.जे. 615.

पूर्व-मुक्ति की मांग की थी, जिसे विद्वान ट्रायल कोर्ट ने मुख्य रूप से इस आधार पर खारिज कर दिया था कि सीमा अवधि की समाप्ति के कारण विक्रेताओं को मूल्यवान अधिकार प्राप्त हुआ था और ऐसे संशोधन की अनुमति नहीं दी जा सकती जो उन्हें उस अधिकार से वंचित कर देगा। गेम आदेश के अनुसार, विद्वान ट्रायल कोर्ट ने मुकदमे को आंशिक प्री-एम्प्शन के रूप में खारिज कर दिया, जिसकी कानून अनुमति नहीं देता था। प्री-एम्प्टर ने जिला न्यायाधीश की अदालत में एक अपील दायर की, जिसने माना कि ट्रायल कोर्ट ने वादी को इस तथ्य के मद्देनजर वादी को संशोधित करने की अनुमति नहीं दी थी कि वादी ने स्पष्ट रूप से संकेत दिया था कि उसका दावा पूर्व-विक्रय-पत्र में शामिल संपत्ति पर छूट का विस्तार किया गया था जिसे वादपत्र में संलग्न किया गया था। विद्वान जिला न्यायाधीश के अनुसार, भट्टियांवाला कुएं में विशेष रूप से हिस्सा मांगने में वादी की विफलता केवल असावधानी के कारण उत्पन्न हुई थी। अपील को विद्वान जिला न्यायाधीश द्वारा स्वीकार कर लिया गया था और उस डिक्री के खिलाफ इस न्यायालय में एक अपील दायर की गई थी और एक विवाद उठाया गया था कि विद्वान जिला न्यायाधीश को वादपत्र में संशोधन की अनुमति नहीं देनी चाहिए थी। उस विवाद से निपटते समय, विद्वान न्यायाधीश ने रिपोर्ट के पैराग्राफ 3 में कहा: -

"वर्तमान मामले में अनुमति दिए गए संशोधन में किसी भी नई पार्टी या प्री-एम्प्शन का एक नया आधार जोड़ने की मांग नहीं की गई थी, बल्कि केवल उस संपत्ति का विवरण जोड़ने की मांग की गई थी जो मूल मसौदे में अनजाने में छोड़ दी गई थी, हालांकि इस मुकदमे के लिए निर्धारित सीमा अवधि समाप्त होने के बाद संशोधन की मांग को अनुमति दी गई थी।। उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए इसमें कोई संदेह नहीं कि यह चूक अनजाने में हुई थी। मूल रूप से प्रस्तुत वादपत्र में दी गई संपत्ति का विवरण बिक्री-पत्र के उस हिस्से के समान है जो विचार के बारे में विवरण से पहले है और सिंचाई के साधनों सहित बेची गई संपत्ति का पूरा विवरण देने का इरादा रखता है, अर्थात्, कुआँ वर्ग संख्या 36 के किला नंबर 26 में स्थित है। भट्टियांवाला कुएं का संदर्भ विक्रय-पत्र के अगले भाग में दिखाई देता है, जिसे आमतौर पर बेची गई संपत्ति के विवरण का पता लगाने के उद्देश्य से संदर्भित नहीं किया जाएगा। तथ्य यह है कि इस तरह का विवरण दस्तावेज़ के पहले भाग में विस्तार से दिया गया था और सामान्य परिश्रम का उपयोग करने वाला व्यक्ति यह मानने का हकदार होगा कि बेची गई संपत्ति को बिक्री-पत्र में एक स्थान पर एक सारगर्भित रूप में वर्णित किया गया था और वह

इसके विवरण को विभाजित नहीं किया जाएगा ताकि इसका एक बड़ा हिस्सा उपयुक्त खंड में उल्लेखित हो और एक छोटा भाग दस्तावेज़ के अंत में दिखाई देने वाले किसी अन्य खंड में हो। मामले के इस दृष्टिकोण में, प्री-एम्प्टर की ओर से उठाई गई दलील कि मूल रूप से तैयार किए गए वादी में भट्टियांवाला कुएं का उल्लेख करने की चूक असावधानी के कारण हुई थी, इसे बिना तथ्य के नहीं कहा जा सकता है और विद्वान जिला न्यायाधीश के पास इसके लिए पूर्ण औचित्य था। इस तथ्य के बावजूद कि मुकदमा शुरू करने की समय सीमा पहले ही समाप्त हो चुकी थी, इस पर कार्रवाई की जा रही है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि वादी की ओर से बेची गई संपत्ति के किसी भी हिस्से पर अपना दावा छोड़ने का कोई इरादा इस तथ्य के बावजूद नहीं लिखा जा सकता है कि भट्टियांवाला कुएं का कोई संदर्भ नहीं दिया गया था। उन्होंने निस्संदेह भुगतान की गई कीमत 12,000 रुपये बताई, लेकिन फिर उन्होंने यह भी कहा कि प्रत्यक्ष कीमत 24,000 रुपये थी। वादी के अनुसार, यह कीमत उस सौदे के संबंध में भुगतान की गई पूरी राशि थी, जिसे वह समग्र रूप से अपने कब्जे में लेना चाहता था। इन परिस्थितियों में, बेची गई संपत्ति के हिस्से के रूप में भट्टियांवाला चाह को निर्दिष्ट करने की चूक से उत्पन्न त्रुटि को सुधारने की अनुमति और पूर्व-खाली की मांग को विक्रेता-प्रतिवादियों को उस अधिकार से वंचित करने के रूप में नहीं माना जा सकता है जो उन्हें प्राप्त हुआ है। समय की चूक भले ही ऐसी अनुमति मुकदमे के लिए निर्धारित सीमा अवधि के बाद दी गई हो, क्योंकि यह केवल एक निर्देश के समान है कि वादी अपने मामले को अपने वास्तविक इरादे के अनुसार बताता है।"

(15) उस मामले के तथ्य स्पष्ट रूप से भिन्न हैं। जैसे ही प्रतिवादियों द्वारा आपत्ति उठाई गई, प्री-एम्प्टर ने संशोधन के लिए एक आवेदन दायर किया और यह नहीं कहा जा सकता कि वह आवेदन प्रामाणिक नहीं किया गया था।

(16) कलवंत सिंह और अन्य बनाम शेर सिंह और अन्य[11], न्यायमूर्ति गुरदेव सिंह का एक निर्णय है, जिसमें उन्होंने अपने फैसले का पालन किया है जो हमारे समक्ष अपील के अधीन है और इसलिए,

---

[11] 1971 पी.एल.जे. 218.

कोई मदद नहीं है। इसके बाद भगवान सिंह और अन्य बनाम कश्मीर सिंह[12] मामले में न्यायमूर्ति पी. सी. पंडित की टिप्पणियों पर भरोसा किया गया, जो रिपोर्ट के पैराग्राफ 8 में निम्नानुसार है: -

"पूर्व-खाली के मामलों में, क्या सीमा के बाद संशोधन की अनुमति दी जानी चाहिए या नहीं, ऐसी परिस्थितियों में, असली परीक्षा यह है कि क्या चूक जानबूझकर या अनजाने में की गई थी। प्री-एम्प्टर का इरादा क्या था? क्या वह पूरा सौदा या उसका एक हिस्सा पहले ही चुका रहा था? यह शिकायत को समग्र रूप से पढ़कर निर्धारित किया जा सकता है। क्या इससे पता चलता है कि वह बेची गई संपत्ति का कोई भी हिस्सा नहीं छोड़ रहा था और पूरी संपत्ति लेने के लिए तैयार था? यदि ऐसा है, तो, यदि वादपत्र में संपत्ति का वर्णन करते समय कुछ चीज़ छूट जाती है, तो यह स्पष्ट रूप से असावधानी या अनजाने में चूक का मामला होगा। जैसा कि मैंने पहले ही कहा है, वर्तमान मामले में, वादपत्र स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि प्री-एम्प्टर बिक्री में शामिल सौदेबाजी के लिए मुकदमा कर रहा था, न कि इससे कम के लिए। वह जानबूझकर इसका कोई भी हिस्सा नहीं छोड़ रहा था। उनका इरादा संशोधन के लिए आवेदन से और भी स्पष्ट है जो उन्होंने लिखित बयान में प्रतिवादियों द्वारा इस मामले के संबंध में आपत्ति उठाए जाने के तुरंत बाद दायर किया था, हालांकि बहुत अस्पष्ट तरीके से और कोई विवरण दिए बिना। उल्लेखनीय है कि अपने साक्ष्य में भी प्रतिवादी ने अपनी आपत्ति स्पष्ट नहीं की। मेरे विचार में, यह वादी में बेची गई संपत्ति के गलत विवरण का मामला था और संपत्ति के अन्य विवरण देने में चूक जानबूझकर नहीं की गई थी। यह आकस्मिक था और प्री-एम्प्टर की ओर से असावधानी और वास्तविक गलती के कारण था। इन परिस्थितियों में, विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ने वादपत्र में संशोधन की सही अनुमति दी थी। यह निर्विवाद है कि यदि संशोधन की अनुमति दी गई होती
कानून के अनुसार, यह नहीं माना जा सकता कि मुकदमा किसके लिए था
आंशिक छूट।" (जोर दिया गया)।

(17) रिपोर्ट के पैराग्राफ 3 में, यह कहा गया है कि लिखित बयान में प्रतिवादियों द्वारा उठाई गई आपत्ति केवल यह थी कि मुकदमा आंशिक प्री-एम्प्शन के लिए था और केवल उसी स्कोर पर

[12] 1971 पी.एल.जे. 222.

खारिज किया जा सकता था। यह नहीं बताया गया कि ऐसा कैसे हुआ। रिपोर्ट के पैराग्राफ 7 में आगे कहा गया है:-

"प्रतिवादियों ने लिखित बयान में कहा कि मुकदमा आंशिक छूट के लिए था। प्री-एम्प्टर उक्त मुकदमे को मूल रूप से तय किए गए अनुसार आगे बढ़ाने पर कायम नहीं रहा। दूसरी ओर, अत्यधिक सावधानी के तौर पर, उन्होंने वाद में संशोधन के लिए एक आवेदन दायर किया जिसमें दोहराया गया कि वह सभी अनुलग्नक और सहायक संपत्ति के साथ बेची गई पूरी संपत्ति पर दावा कर रहे हैं। (जोर दिया गया)।

(18) विद्वान न्यायाधीश के फैसले में प्रमुखता से सामने लाए गए ये दो कारक वर्तमान मामले की तुलना में उस मामले की विशिष्ट विशेषताओं को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं। इसलिए, मेरी राय है कि विद्वान निचली अपीलीय अदालत ने वादी को अपने वादपत्र में संशोधन करने की अनुमति देकर और उसके परिणामस्वरूप अपील में उसके मुकदमे पर पूरी तरह से फैसला सुनाकर अवैधता की है। उन्हीं कारणों से, और मैं सम्मान के साथ ऐसा कहता हूं, दूसरी अपील में विद्वान एकल न्यायाधीश ने यह मानने में गलती की कि प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा संशोधन को सही तरीके से अनुमति दी गई थी।

(19) वादी-प्रतिवादी के विद्वान वकील ने तब तर्क दिया कि विद्वान निचली अपीलीय अदालत द्वारा प्रयोग किए गए विवेक को इस न्यायालय द्वारा अपील में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। बट्टू मल बनाम रामेश्वर नाथ और अन्य[13] में दिल्ली उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच के फैसले पर भरोसा किया गया है, जिसमें इसे हेड-नोट 'डी' के अनुसार निम्नानुसार रखा गया था: -

"आम तौर पर यह उस ट्रिब्यूनल के विवेक पर निर्भर करता है, जिसमें संशोधन के लिए आवेदन किया गया है कि वह उसे अनुमति दे या अस्वीकार कर दे। उच्च न्यायालय विवेकाधिकार में हस्तक्षेप नहीं करेगा जब तक कि इसका प्रयोग अवैध रूप से या असमान रूप से नहीं किया गया हो।"

---

[13] ए.आई.आर.1971 दिल्ली 98.

(20) मेरा इस प्रस्ताव से कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन इस मामले के तथ्यों पर, विद्वान निचली अपीलीय अदालत द्वारा विवेक का अवैध और असमान रूप से प्रयोग किया गया था और अपील में इसमें हस्तक्षेप किया जा सकता है। वास्तव में, मामला दूसरी अपील में विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष उठाया गया था और, मेरी राय में, उनका निर्णय कि संशोधन को सही तरीके से अनुमति दी गई थी, गलत है। इसलिए, मुझे इस बिंदु पर विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले को पलटने में कोई हिचकिचाहट नहीं है।

(21) अंत में, वादी-प्रतिवादी के लिए विद्वान वकील द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि संशोधन की अनुमति देने वाले आदेश से प्रतिवादी अपीलकर्ताओं के साथ कोई अन्याय नहीं हुआ है और वादी द्वारा संशोधन के लिए आवेदन को विद्वान निचली अपीलीय अदालत द्वारा दी गई लागत ने उन्हें देरी के लिए पर्याप्त मुआवजा दिया है। मुझे खेद है कि मैं इस निवेदन से सहमत नहीं हो सका। आंशिक प्री-एम्प्शन का मुकदमा सक्षम नहीं है और ऐसे मुकदमे को खारिज कर दिया जाना चाहिए और यदि इसे उस आधार पर खारिज कर दिया जाता है, तो प्रतिशोधी-प्रतिवादियों को एक बहुत ही मूल्यवान अधिकार प्राप्त होता है, क्योंकि उस संपत्ति को बनाए रखने का उनका अधिकार अपरिहार्य हो जाता है। यदि वादपत्र में संशोधन की अनुमति देकर उस अधिकार को ख़तरे में डाल दिया जाता है, तो उनके साथ घोर अन्याय होता है जिसकी भरपाई लागत के पुरस्कार से नहीं की जा सकती। वास्तव में, मुकदमा खारिज होने के बाद, इस मामले में वादी के आचरण को देखते हुए संशोधन की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए थी, जिसका संदर्भ ऊपर दिया गया है। तदनुसार, मेरी राय है कि विद्वान निचली अपीलीय अदालत ने वाद में संशोधन की अनुमति देकर कानून में गलती की है और विद्वान एकल न्यायाधीश ने भी यह मानकर कानून में गलती की है कि संशोधन को सही तरीके से अनुमति दी गई है।

(22) अंतिम उपाय के रूप में, वादी-प्रतिवादी के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि वास्तव में वादी को किसी भी संशोधन की आवश्यकता नहीं है क्योंकि बेची गई पूरी संपत्ति को मुकदमे की विषय-वस्तु बना दिया गया था जैसा कि वाद पत्र के अंतिम पैराग्राफ जो की राहतों से संबंधित है में कहा गया है।उस अनुच्छेद में, यदि यह कहा गया है:-

"वादी प्रार्थना करता है कि पट्टी डोगरान, कैथल में स्थित 307 कनाल 6 मरला कृषि भूमि, जो खेवट नंबर 14, खतौनी नंबर 17, 18, किला नंबर में शामिल है, जैसा फर्द जमाबंदी 1961-62 में उल्लेखित है, को कब्जे में लेने का आदेश जारी किया जाए, अन्य सहायक अधिकारों और कोठों आदि के साथ, जैसा कि वादपत्र के पैरा नंबर 2 में बिक्री विलेख में उल्लिखित है, 38,605 रुपये या किसी अन्य राशि के भुगतान पर, जिसे न्यायालय उस भुगतान पर उचित समझे, दी जाएगी।"

यह अनुच्छेद स्पष्ट रूप से उस संपत्ति को संदर्भित करता है जैसा कि जमाबंदी 1961-62 और विक्रय पत्र में उल्लिखित है और वादी के अनुच्छेद 2 में वर्णित है। इसलिए, जिस संपत्ति को मुक्त कराने की मांग की गई है, उसका पता लगाने के लिए हमें मजबूरन वादी के पैरा 2 में उल्लिखित बातों का उल्लेख करना होगा। उस पैरा में "कोठा खाम और एक पक्का" का उल्लेख है। वादी का इरादा बिल्कुल स्पष्ट है कि वह 5 कोठे खाली कर रही थी, 6 नहीं। उस इरादे को प्रतिकृति में उसके स्पष्ट दावे से और भी स्पष्ट किया गया है कि "कोठे केवल पांच थे जैसा कि बिक्री की प्रति में उल्लिखित है।" वादपत्र के अनुच्छेद 7 में मुकदमा किए गए सभी कोठों का बाजार मूल्य 100 रुपये बताया गया था, जिसे बाद में मूल्यांकन के संबंध में मुद्दा संख्या 2 पर निर्णय होने पर 500 रुपये में बदल दिया गया था। यह मूल्य विवादित कोठों का था, बेचे गए सभी कोठों का नहीं। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि वादी ने विक्रय पत्र में उल्लिखित सभी कोठों के लिए मुकदमा नहीं किया था, बल्कि केवल 5 कोठों के लिए मुकदमा किया था, जैसा कि वाद पत्र के पैराग्राफ 2 में उल्लिखित है और आंशिक पूर्व-खाली की आपत्ति से बचने के लिए, वाद में संशोधन की आवश्यकता थी। इस प्रकार यह प्रस्तुतीकरण निरस्त किया जाता है।

(23) थेरेनिस्ट ने जिस तरीके से वादी ने संशोधन की अनुमति दी, उसे लागू करने के तरीके में एक और अवैध कमजोरी थी। उसने वादपत्र के पैराग्राफ 2 में अंक 4 को अंक 5 से प्रतिस्थापित कर दिया, लेकिन अदालत-शुल्क और अधिकार क्षेत्र के प्रयोजनों के लिए छठे कोठा के मूल्यांकन के संबंध में वादपत्र के अनुच्छेद 7 में तदनुरूपी संशोधन नहीं किया और न ही कोई अतिरिक्त अदालत-शुल्क का भुगतान किया गया। जैसा कि मूल वादपत्र में उल्लिखित है, दोनों पक्षों के विद्वान वकील के बयान के अनुसार पाँच कोठों का मूल्य 500 रुपये निर्धारित किया गया था। छठे

कोठे को शामिल करने के बाद, वादी का यह कर्तव्य था कि वह इसका मूल्य बताए और उस पर अदालत-शुल्क का भुगतान करे। ऐसा नहीं करने पर, वादपत्र में किया गया संशोधन अधूरा रह गया और वादी को अतिरिक्त कोठा के लिए डिक्री का अधिकार नहीं मिला। मुक़दमा आंशिक छूट के दोष से ग्रस्त रहा और उस पर फैसला नहीं सुनाया जा सका।

(24) चूंकि ऊपर तय किया गया कानून का बिंदु ही एकमात्र ऐसा बिंदु है जो अपील में अनिर्णीत रहा, इसलिए ऊपर व्यक्त राय के अनुसार अंतिम निर्णय पारित करने के लिए इसे डिवीजन बेंच को वापस भेजने का कोई मतलब नहीं है, मैं तदनुसार इस अपील को स्वीकार करता हूं और वादी-प्रतिवादी के मुकदमे को खारिज कर दें, और पार्टियों को पूरी लागत स्वयं वहन करने के लिए छोड़ दें।

न्यायमूर्ति महाजन- मैं सहमत हूं।

न्यायमूर्ति सूरी-(25) मैं अपने विद्वान भाइयों से सहमत हूं कि, वर्तमान मामले के तथ्यों पर, वादी-प्रतिवादी संख्या 1 को अपीलीय चरण में अपने वाद में संशोधन करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए थी, लेकिन यह बहुत व्यापक प्रस्ताव होगा कानून को एक सामान्य नियम के रूप में निर्धारित किया जाना चाहिए कि एक वादी-प्री-एम्प्टोर जिसने परीक्षण के दौरान वाद में संशोधन के लिए आवेदन नहीं किया है, आंशिक प्री-एम्प्शन के बारे में आपत्ति के बाद विपरीत पक्ष द्वारा प्रारंभिक चरण में ले लिया गया था। अपीलीय चरण में संशोधन की मांग करने से रोका जाएगा। किसी डिक्री की अंतिमता जिसे अपील या पुनरीक्षण में चुनौती दी गई है, अधर में लटकी हुई है और ऐसी डिक्री को इस अर्थ में किसी पार्टी में कोई निहित अधिकार बनाने के लिए नहीं माना जा सकता है कि डिक्री के पारित होने से पहले एक संशोधन की अनुमति दी जा सकती थी। डिक्री पारित होने के बाद इसे बनाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। अन्यथा धारण करना न्यायालयों की हाल की प्रवृत्ति को नजरअंदाज करने जैसा होगा जो सभी चरणों में दलीलों में संशोधन की अनुमति देता है यदि यह दूसरे पक्ष के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना किया जा सकता है और यदि उस पक्ष को देरी और असुविधा के लिए लागत प्रदान करने वाले आदेश द्वारा कार्यवाही में मुआवजा दिया जा सकता है ।

(26) हाल ही में, अदालतें दलीलों में संशोधन की अनुमति देने के मामले में उदार होने की ओर झुक रही हैं ताकि पक्षों के बीच पर्याप्त न्याय हो सके। जय जय राम मनोहर लाई, बनाम राष्ट्रीय भवन निर्माण सामग्री आपूर्ति, गुड़गांव[14] में, सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश यह देखकर प्रसन्न थे कि प्रक्रिया के नियमों का उद्देश्य न्याय प्रशासन के लिए सहायक होना है। केवल किसी गलती, लापरवाही, असावधानी या यहां तक कि प्रक्रिया के नियमों के उल्लंघन के कारण किसी पक्ष को राहत देने से इनकार नहीं किया जा सकता है। न्यायालय हमेशा किसी पक्ष की दलील में संशोधन करने की अनुमति देता है, जब तक कि वह संतुष्ट न हो जाए कि आवेदन करने वाला पक्ष दुर्भावनापूर्ण कार्य कर रहा था, या अपनी गलती से, उसने अपने प्रतिद्वंद्वी को चोट पहुंचाई थी, जिसकी भरपाई लागत के आदेश से नहीं की जा सकती थी। पहली चूक चाहे कितनी ही लापरवाहीपूर्ण या लापरवाह क्यों न रही हो, और प्रस्तावित संशोधन में कितनी भी देर क्यों न हुई हो, संशोधन की अनुमति दी जा सकती है यदि इसे दूसरे पक्ष के साथ अन्याय किए बिना किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का न्यायमूर्ति सरकारिया ने मैसर्स में पालन किया। पंजाब राजस्थान टिम्बर ट्रेडिंग कंपनी बनाम द वेयर वेल साइकिल कंपनी इंडिया लिमिटेड[15], और फिर हरबंस सिंह, सी.जे. द्वारा, रघवीर प्रसाद आदि बनाम चेत राम[16]। अंतिम उल्लिखित फैसले में, यह आगे देखा गया कि यदि विपरीत पक्ष को लागत के भुगतान के आदेश द्वारा मुआवजा दिया जा सकता है तो संशोधन के कारण कोई अन्याय नहीं होता है और वादी को कार्रवाई का एक नया कारण जोड़ने की भी अनुमति दी जा सकती है और प्रतिवादी को एक नया बचाव जोड़ना होगा और कार्यवाही के बहुत देर के चरण में भी एक नया मामला पेश करने की अनुमति देने पर कोई रोक नहीं होगी। केवल यह तथ्य कि कार्रवाई का कारण बदल दिया गया था, संशोधन को अस्वीकार करने का कोई आधार नहीं था। मैसर्स द पंजाब राजस्थान टिम्बर ट्रेडिंग कंपनी के मामले (15), (सुप्रा) में, सीमा की वैधानिक अवधि की समाप्ति के बाद भी एक संशोधन करने की अनुमति इस आधार पर दी गई थी कि संशोधन ने मुकदमे की प्रकृति को नहीं बदला है। लेकिन यह मामले के प्रति एक अलग या अतिरिक्त दृष्टिकोण मात्र था। इन फैसलों में यह सुझाव देने के लिए कुछ भी नहीं है कि निर्धारित

---

[14] ए.आई.आर.1969 एस.सी. 1267.

[15] 1970 पाठ्यक्रम एल.जे. 322।

[16] 1971 पाठ्यक्रम एल.जे. 612।

कानून के सिद्धांतों का मूल अनुपात किसी विशेष श्रेणी के मामलों पर लागू करने का इरादा था या प्री-एम्प्शन मामले में दलीलों के संशोधनों को किसी भी अलग मानकों द्वारा शासित किया जाना था। मैं इस तथ्य से अवगत हूं कि प्री-एम्प्शन के अधिकार को कई स्थानों पर समुद्री डाकू अधिकार के रूप में वर्णित किया गया है, लेकिन जब तक क़ानून इसे मान्यता देता है, यह एक कानूनी अधिकार है और इसे वैध तरीकों के अलावा अन्यथा पराजित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

(27) मैं वर्तमान मामले के कुछ पहलुओं पर ध्यान देना चाहूंगा जो उन परिस्थितियों का स्पष्ट विचार दे सकते हैं जिनके तहत वादी-प्री-एम्प्टर ने प्रथम अपील की अदालत में अपने वाद में संशोधन की मांग की थी। विक्रय विलेख, एक्ज़िबिट डी. 2, हमेशा की तरह विक्रेताओं के नाम और माता-पिता आदि देकर शुरू होता है। इसके बाद बेची गई संपत्ति का विवरण दिया गया है जिसमें मुख्य रूप से कृषि भूमि शामिल है। यह विक्रय विलेख में सामान्य स्थान है जहां कोई आम तौर पर बेची गई संपत्ति का पूरा विवरण ढूंढता है। इस स्थान पर, विक्रय पत्र में उल्लेख किया गया है कि भूमि और कुछ सहायक अधिकारों के अलावा, चार कोठा खाम और एक कोठा पुख्ता विक्रेताओं को बेच दिया गया था। बेची गई संपत्ति का यह विवरण प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा दायर वादपत्र में सटीक रूप से प्रस्तुत किया गया था। विक्रय विलेख, प्रदर्शनी डी. 2, देवनागरी लिपि में हिंदी में लिखा गया एक लंबा दस्तावेज़ है और दस्तावेज़ को पढ़ते समय मेरे जैसे अधिकांश लोगों ने इसे पढ़ा होगा। जब तक वे विक्रय पत्र के मुख्य भाग की अंतिम पंक्ति तक पहुँचे, तब तक उनका धैर्य समाप्त हो चुका था, जहाँ यह उल्लेख किया गया है, पहले के विवरण के अनुरूप नहीं, कि भूमि पर छह कोठे हैं जो विक्रेताओं को बेच दिए गए हैं। प्रतिवादी नंबर 1 ने अपनी शिकायत के पैराग्राफ 2 के अंत में उल्लेख किया था कि बिक्री विलेख की एक प्रति दायर की जाएगी और उसने वास्तव में तारीख से बहुत पहले पंजीकृत बिक्री विलेख की एक प्रमाणित प्रति रिकॉर्ड पर रखी थी, जिस पर अपीलकर्ता-विक्रेता ने मामले में अपना लिखित बयान दर्ज कराया था। प्रमाणित प्रति प्रदर्शनी पी. 2 के रूप में चिह्नित है और वादी के वकील द्वारा 8 अक्टूबर, 1965 को अदालत में दायर की गई थी। प्रतिवादियों द्वारा दायर लिखित बयान पर तारीख 11 जनवरी, 1966 अंकित है। इसलिए, महिला को इसके लिए लापरवाह नहीं ठहराया जा सकता है। उसके वकील द्वारा इस बिक्री विलेख की एक

सच्ची प्रति अपने ब्रीफ में रखने में विफलता। वादी के पैराग्राफ 2, 5 और 8 में महिला ने यह स्पष्ट कर दिया था कि वह सभी सहायक अधिकारों के साथ बेची गई पूरी संपत्ति को पहले से खाली करना चाहती थी और उसने विलेख में उल्लिखित पूर्ण बिक्री मूल्य का भुगतान करने की पेशकश की थी। कोई भी संपत्ति का एक हिस्सा छोड़ना नहीं चाहेगा और फिर भी इसकी कीमत का भुगतान करने की पेशकश करेगा और वादी का इरादा स्पष्ट था कि वह पूरे सौदे को पहले से चुकाना चाह रही थी। छठे कोठे को शामिल करने की चूक, जिसका उल्लेख विक्रय पत्र, प्रदर्शनी डी. 2 में लेखन के मुख्य भाग की केवल अंतिम पंक्ति में किया गया था, स्पष्ट रूप से अनजाने में थी।

(28) प्रतिवादियों ने अपने लिखित बयान में चार प्रारंभिक आपत्तियां ली थीं। इनमें से एक आपत्ति न्यायालय शुल्क और क्षेत्राधिकार के प्रयोजनों के लिए मुकदमे के मूल्यांकन के संबंध में थी। दूसरी आपत्ति यह थी कि मुकदमा आंशिक पूर्व-मुक्ति के लिए ख़राब था। कहीं भी यह स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया कि बेची गई संपत्ति में जमीन और छह कोठे शामिल थे। न्यायालय शुल्क और क्षेत्राधिकार के प्रयोजनों के लिए भूमि का मूल्य भू-राजस्व के दस और तीस गुना पर निर्धारित किया गया था, लेकिन न्यायालय शुल्क कोठों के बाजार मूल्य पर यथामूल्य देय था। लिखित बयान में, यह कहा गया था कि कोठों की कीमत 1,000 रुपये से कम नहीं थी और यह राशि विवाद में कोठों के मूल्य के रूप में आपसी सहमति से अंततः सहमत राशि की तरह संख्या छह का सटीक गुणक नहीं थी। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि लिखित बयान में यह स्पष्ट रूप से सामने नहीं आया है कि आंशिक प्री-एम्प्शन के लिए मुकदमा किस प्रकार खराब था।

(29) वादी-प्री-एम्प्टर ने एक प्रतिकृति दायर की जिसमें उसने सभी प्रारंभिक आपत्तियों का खंडन किया। प्रथम अपील न्यायालय में दायर वादपत्र में संशोधन के लिए आवेदन में किए गए कथनों के अनुसार, यह निचली अदालत में वादी के अधिवक्ता द्वारा रखे गए विक्रय पत्र की एक गलत प्रति के आधार पर किया गया था। पक्षों को इस आवेदन के संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए नहीं बुलाया गया था और बिक्री विलेख की अधूरी या गलत प्रति अदालत में पेश करने का अवसर ही नहीं आया था। आवेदन में दिए गए कथन को स्पष्ट रूप से न्यायालय द्वारा सही माना गया था जब लागत के रूप में 100 रुपये के भुगतान पर संशोधन करने की अनुमति दी गई थी। ऊपर उद्धृत

निर्णयों के आधार पर, मुझे यह कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि इस विवेक का उचित रूप से प्रयोग किया गया था और वादी-प्री-एम्प्टर की ओर से गलती अनजाने और प्रामाणिक थी।

(30) हालाँकि, यह नहीं कहा जा सकता है कि वर्तमान मामले में लागत निर्धारण आदेश द्वारा विपरीत पक्ष को मुआवजा दिया जा सकता था। ऐसा प्रतीत हो सकता है कि वादी-प्री-एम्प्टर ने ट्रायल कोर्ट में अपने आचरण से खुद के खिलाफ एक बाधा खड़ी कर दी थी, जिसने उसे अपीलीय अदालत में वाद में संशोधन की मांग करने से रोक दिया था। प्रथम दृष्टया अदालत में उसके आचरण ने प्रतिवादियों के मन में यह विश्वास पैदा कर दिया था कि वह मुकदमे में गलती या चूक के बावजूद छठे कोठे का कब्ज़ा लेने के लिए तैयार नहीं थी। छठे कोठे को विवादग्रस्त संपत्ति के रूप में वर्णित नहीं किया जा सकता था यदि वह इस पर कोई दावा नहीं कर रही थी। ट्रायल कोर्ट में पिछली सुनवाई पर, वादी-प्री-एम्प्टर के आचरण से प्रेरित इस गलत विश्वास पर काम करने वाले प्रतिवादियों को कोर्ट शुल्क और क्षेत्राधिकार के प्रयोजनों के लिए मुकदमे के कम मूल्यांकन पर सहमत होने के लिए मजबूर किया गया था। ऐसा प्रतीत हो सकता है कि इन तथ्यों ने वादी द्वारा वाद में संशोधन की मांग के विरुद्ध विबंधन की बाधा उत्पन्न कर दी है, जब प्रतिवादियों ने अपनी स्थिति को उनके नुकसान या पूर्वाग्रह के लिए बदल दिया था और उन्हें कम मूल्यांकन पर सहमत होने के लिए सहमत किया गया था, यदि वाद पत्र में छठे कोठे पर सहमति हो सकती थी। किसी की गलती पर बने रहने पर दो तरीकों में से किसी एक में दंडित किया जा सकता है, अर्थात्, गलती करने वाले पक्ष को या तो लागत के रूप में पर्याप्त राशि का भुगतान किया जा सकता है, जिसे विपरीत पक्ष को देरी और असुविधा के लिए मुआवजे के रूप में भुगतान किया जा सकता है। कार्यवाही या गलती करने वाले पक्ष से उसके कानूनी अधिकार पूरी तरह छीने जा सकते हैं। उत्तरार्द्ध एक कठोर और गंभीर रास्ता होगा जिसका सहारा केवल तभी लिया जा सकता है जब विपरीत पक्ष को अन्यथा मुआवजा नहीं दिया जा सकता है। अप्राकृतिक तरीके से मुकदमे को समाप्त करने की तुलना में पक्षों को पर्याप्त न्याय दिलाना अधिक महत्वपूर्ण है। इसलिए, मैं केवल इस बात से सहमत हूं कि मामले के विशिष्ट तथ्यों पर इस अपील को स्वीकार किया जाना चाहिए और वादी-प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा दायर प्री-एम्प्शन सूट को खारिज कर दिया जाना चाहिए और पार्टियों को अपनी लागत वहन करनी चाहिए। हालाँकि, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि हम सार्वभौमिक अनुप्रयोग का एक नियम

बना सकते हैं कि उन सभी मामलों में जहाँ एक प्री-एम्प्टर परीक्षण के दौरान अपने वाद में संशोधन की मांग करने में विफल रहा है, जब विपरीत पक्ष ने आंशिक दोष की ओर इशारा किया था। प्रारंभिक चरण में प्री-एम्प्शन, उसे अपीलीय चरण में उस संशोधन की मांग करने से रोक दिया जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर प्रत्येक व्यक्तिगत मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

स्मृति

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

कुरूक्षेत्र, हरियाणा